

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

//आदेश //

मानव संस्कृति विभाग 22/07/09

क्रमांक एफ 20-38/08/बी/ग्यारह : इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 20-46/03/बी/ग्यारह, दिनांक 24.10.07 द्वारा उद्योग रांचीन नीति, 2004 एवं कार्ययोजना (रांशोधित) जारी की गई थी जो दिनांक 31/03/09 तक प्रभावशील रही है।

2. राज्य शासन द्वारा उक्त उद्योग रांचीन नीति, 2004 एवं कार्ययोजना के प्रभावशील रहने की अनुमति दिनांक 1-4-2009 से दिनांक 31-12-2009 अथवा नवीन रांशोधित/पुनरीक्षित उद्योग नीति के प्रभावशील होने के दिनांक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाती है। इसके परिणामरक्ख प्रभावशील रहने की अवधि में जो इकाईयां उत्पादन में आती है उन्हें नई सुविधाएं प्राप्त होंगी जो कि दिनांक 01/04/09 के पूर्व उत्पादन में आने वाली इकाईयों को अप्राप्य हो रही थी।

3. उद्योग-संवर्धन नीति, 2004 एवं कार्ययोजना की अवधि दिनांक 01/04/09 से दिनांक 31/12/09 अथवा संशोधित/पुनरीक्षित उद्योग नीति के प्रभावशील होने के दिनांक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाने पर नीति के अनुसार उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं/सहायता दिये जाने से संबंधित अधिकृतों/सूचनाओं/आदेशों (जो अन्य विभागों से भी संबंधित होंगे) की अवधि संबंधित विभागों द्वारा तदनुरूप बढ़ाई जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंवरी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 22/07/09

पृष्ठ ०१ क्रमांक 20-38/08/बी/ग्यारह

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म०प्र० ट्रैड इनवेर्सेंट फेसिलिटेशन कार्परिशन लिं०/ म०प्र० म.प्र.सेट इण्डियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिं०, भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
संत्रालयः
// आदेश //
भोपाल, दिनांक २२ जनवरी, 2010

इस अधिकारीकृत आदेश के अनुसार इस विभाग के अधीन, दिनांक 22.07.2009
के उद्योग संचालन नीति 2004 एवं कार्य योजना (संसाधित) की प्रभावशालता की
अवधि, दिनांक 01.04.2009 से दिनांक 31.12.2009 अवधि नवीन संसाधित / पुनर्रक्षित
उद्योग नीति के प्रभावशालित होने के दिनांक जो भी पहले हो, तक बढ़ाई राई थी।

१/ नव राज्य शासन द्वारा उद्योग संचालन नीति 2004 एवं कार्य योजना की
प्रभावशालता को अवधि दिनांक 31.03.2010 तक बढ़ाई जाती है। परिणाम इससे
दिनांक 01.01.2010 से इस नीति के प्रभावशाल रहने की अवधि में जो इकाईयों
उत्पादन में आती है, उन्हें वही सुविधायें प्राप्त होगी जो दिनांक 01.01.2010 के पूर्व
उत्पादन में आने वाली इकाईयों को उपलब्ध हो रही थी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम पर तथा
आदेशानुसार

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक २२-१-१०

पृ. क्रमांक एफ-२०--३८/०८/बी-ग्यारहः

प्रतिलिपि:-

१/ अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मध्यप्रदेश शासन
संत्रालय, भोपाल।

२/ उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, भोपाल।

३/ प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन
लिमिटेड, भोपाल / मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग